



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 599]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 2017/आषाढ़ 14, 1939

No. 599]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 2017/ASADHA 14, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2017

सं. 64/2017-सीमाशुल्क

**सा.का.नि. 833(अ).**—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए विशेष आर्थिक जोन में की किसी इकाई या किसी विकासकर्ता द्वारा आयात किए गए सभी माल को, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्गृहणीय संपूर्ण एकीकृत कर से छूट प्रदान करती है।

[फा.सं.डीजीईपी/एसईजेड/09/2017]

धर्मवीर शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2017

No. 64/2017- Customs

**G.S.R. 833(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods imported by a unit or a developer in the Special Economic Zone for authorised operations, from the

whole of the integrated tax leviable thereon under sub-section (7) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with section 5 of the Integrated Goods and Service Tax Act, 2017 (13 of 2017).

[F. No. DGEP/SEZ/09/2017]

DHARMVIR SHARMA, Under Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2017

#### सं. 17/2017- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 834(अ).—केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. संख्यांक 740(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 15/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 को, उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जिन्हे ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था।

[फा. सं. डीजीईपी/एसईजेड/09/2017]

धर्मवीर शर्मा, अवर सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2017

#### No. 17/2017 -Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 834(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Service Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 15/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 740 (E), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017.

[F. No. DGEP/SEZ/09/2017]

DHARMVIR SHARMA, Under Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2017

#### सं. 18/2017- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 835(अ).—केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों पर, प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए विशेष आर्थिक जोन में कि किसी

इकाई या किसी विकासकर्ता द्वारा आयात की गई सेवाओं को एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 के अधीन उस पर उदग्रहणीय संपूर्ण एकीकृत कर से छूट प्रदान करती है।

[फा .सं .डीजीईपी/एसईजेड-/09/2017]

धर्मवीर शर्मा, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th July, 2017

**No. 18/2017 -Integrated Tax (Rate)**

**G.S.R. 835(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Service Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do and on the recommendations of the Council, hereby exempts services imported by a unit or a developer in the Special Economic Zone for authorised operations, from the whole of the integrated tax leviable thereon under section 5 of the Integrated Goods and Service Tax Act, 2017 (13 of 2017).

[F. No. DGEP/SEZ/09/2017]

DHARMVIR SHARMA, Under Secy.